



आपदा प्रबंधन में मीडिया की भूमिका का अध्ययन : डा बिजेन्द्र कुमार

एसोसिएट प्रोफेसर , डा भीमराव अंबेडकर कॉलेज
दिल्ली विश्वविद्यालय

सारांश—आपदा प्रबंधन में मीडिया की भूमिका बहुआयामी होती है। मीडिया की भूमिका आपदा के पहले , आपदा के दौरान और बाद भी निरंतर चलती रहती है। प्राकृतिक आपदाओं के संदर्भ में मीडिया की भूमिका को तीन स्तर पर देखा जा सकता है। प्रथम , आपदा के आने से पूर्व की तैयारी , दूसरे , आपदा के दौरान निर्भाई गई भूमिका और तीसरे, आपदा के बाद की परिस्थितियों में मीडिया की भूमिका । तीनों स्तर पर मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कुछ आपदाएं प्रत्याशित होती हैं , तो कुछ अप्रत्याशित होती हैं लेकिन मीडिया का कार्य प्रत्याशित और अप्रत्याशित आपदा का पूर्व आकलन करना और नागरिकों को इसके लिए तैयार करने के साथ शिक्षित करना , राहत और बचाव के प्रयास करना , सटीक , सही , प्रामाणिक और समय पर सूचना देना है। सूचनाओं की यथासमय जानकारी मिलने से जान-माल के नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। सटीक सूचना से आपदा के दौरान राहत और बचाव कार्य की व्यवस्था करने में सुविधा भी रहती है और समय भी कम लगता है। मीडिया की सूचनाएं विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने में सहायक होती है। परंपरागत और सोशल मीडिया में आपदा प्रबंधन से जुड़ी जानकारियाँ पहले की तुलना में अधिक मात्रा में आने लगी हैं। विशेष रूप से सोशल मीडिया में आपदा से जुड़ी कुछ खबरों में होने वाली राजनीति और उन खबरों की प्रामाणिकता पर सवाल भी उठते रहे हैं।

आपदा में सटीक और प्रामाणिक जानकारी प्रदान करने लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपने जनसम्पर्क और जागरूकता प्रभाग के माध्यम से सोशल मीडिया विशेष तौर पर फेसबुक , यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर टेक्स्ट , ऑडियो , वीडियो , ब्रोशर , पम्पलैट , पोस्टर और नुक्कड़ नाटक जैसे सरल और लोकप्रिय तरीकों का प्रयोग भी किया जाता है। मीडिया में सनसनी को महत्व दिए जाने के कारण एक ओर आपदा को लेकर आंकड़ों का खेल होता है तो दूसरी ओर आपदा का फॉलोअप कम होता जाता है। वैश्विक आपदा में भारतीय मीडिया सूचना के लिए पश्चिमी मीडिया पर अधिक निर्भर रहता है। आपदा रिपोर्टिंग एक जोखिम का काम है लेकिन जनहित और मीडिया के उत्तरदायित्व के कारण अक्सर रिपोर्टर इस जोखिम का निर्वाह करते हैं।

बीज शब्द – आपदा , प्रबंधन , मीडिया , सोशल मीडिया , राहत , बचाव , संवेदनशीलता , फेक न्यूज , विश्वसनीयता , सटीक , सत्य ।

शोध प्रविधि – प्रस्तुत शोध पत्र में परंपरागत और सोशल मीडिया में आपदा प्रबंधन से जुड़ी सामग्री का मात्रात्मक और गुणात्मक दृष्टि से अध्ययन करने का प्रयास किया है। इलैक्ट्रॉनिक , प्रिन्ट और सोशल मीडिया में आपदा पूर्व , आपदा के दौरान और आपदा पश्चात आने वाली सूचनाओं का अध्ययन -विश्लेषण शोध पत्र में करने का प्रयास किया गया है।

शोध क्षेत्र – प्रस्तुत शोध के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं की परंपरागत और सोशल मीडिया में की जाने वाली रिपोर्टिंग का अध्ययन करना है। इनमें इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिन्ट मीडिया और सोशल मीडिया को शामिल किया गया है। परंपरागत और सोशल मीडिया में आपदा से जुड़ी सूचनाएं किन -किन रूपों में या रही है , इसका अध्ययन भी इस शोध पत्र का विषय है।

प्रस्तावना -- आपदा आरंभ से ही मानव जीवन से जुड़ी है। मनुष्य ने प्रकृति की अनेक भीषण आपदाओं से जूझते हुए सभ्यता के विविध चरणों को पार किया है। आपदाएं प्राकृतिक और मानवीय दोनों प्रकार की रहीं हैं जिसके कारण मानव जीवन और संपत्ति को बहुत भारी नुकसान होता रहा है। वस्तुतः आपदा किसी क्षेत्र में हुए उस विध्वंस, अनिष्ट , विपत्ति या बेहद गंभीर घटना से है जो प्राकृतिक या मानवीय कारणों से दुर्घटना वश या लापरवाही से घटित होती है। आपदा के कारण मनुष्य जीवन , संपत्ति और पर्यावरण तीनों प्रभावित होते हैं। आपदा की विकट स्थिति मानवीय, भौतिक , सामाजिक और आर्थिक जीवन पर विपरीत प्रभाव डालती है। आपदाओं के अनेक रूप हैं। कुछ आपदाएं मानव निर्मित होती हैं। इनमें आतंकी घटनाएं , आग, दुर्घटना, युद्ध, संघर्ष, सांप्रदायिक या जाति आधारित हिंसा आदि शामिल हैं। कुछ आपदाएं प्रकृति प्रदत्त होती हैं। इन आपदाओं में जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, चक्रवात तूफान , सुनामी, बाढ़, ओलावृष्टि, बादल फटना, बिजली गिरना, शीतलहर, सूखा , भूस्खलन और सुनामी आदि शामिल हैं। महामारी, कीट आक्रमण , पशु महामारी और जहरीला भोजन आदि जैविक आपदाएं हैं। रसायनिक और दुर्घटना जनित आपदाएं भी मानव जनित हैं। मीडिया में पर्यावरण , जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं पर लगातार चिंता व्यक्त की जाती रही है। भूमंडलीकरण और इंटरनेट तकनीक के समय में आज पहले की तुलना में आपदा पूर्व , आपदा के दौरान और आपदा के बाद अधिक सूचनाएं मीडिया में आने लगी हैं ।

आपदा प्रबंधन – ऐतिहासिक और वैधानिक स्थिति :

आपदा प्रबंधन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसका प्रबंधन व्यक्तिगत, सामाजिक और सरकार सभी स्तर पर किया जाता है। भारत में आपदा प्रबंधन को लेकर गहन चिंतन 1999 में उड़ीसा के तूफान और 2000 में गुजरात में भूकंप के आने के बाद आरंभ हुआ। इन दोनों आपदाओं में हजारों लोगों को जान माल का नुकसान हुआ। देश में आपदा प्रबंधन के लिए एक कानून और संस्था बनाने की आवश्यकता अनुभव की गई। इस दिशा में ठोस कदम उठाते हुए भारत सरकार ने 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाया। इस अधिनियम के माध्यम से विभिन्न मानवीय और प्राकृतिक आपदाओं से बचाव, सुरक्षा और निपटारे के उपाय की रूपरेखा पहली बार वैधानिक रूप से बनाई गई। भारत में पहली बार व्यवस्थित रूप से आपदा जैसे जोखिम से निपटने की व्यवस्थित तैयारी के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई। इस आपदा प्रबंधन कानून के माध्यम से आपदा प्रबंधन को परिभाषित करते हुए अधिनियम में बताया गया कि आपदा प्रबंधन से तात्पर्य योजना, समन्वय और कार्यान्वयन की निरंतर और एकीकृत प्रक्रिया से है जिसमें किसी आपदा के खतरे या उसकी आशंका का निवारण, किसी आपदा या उसकी गंभीरता या उसके परिणामों के जोखिम के शमन की क्षमता निर्माण, किसी आपदा से निपटने की तैयारियां, किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा से तुरंत बचाव, किसी आपदा के प्रभाव की गंभीरता या परिणाम का निर्धारण और आपदा निष्क्रमण, बचाव और राहत आपदा के बाद पुनर्वास और पुनर्निर्माण से है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम में राज्य एवं जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित किए जाने का प्रावधान किया गया। धारा 138 के तहत जिला योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना का प्रदान किया गया जिसमें पंचायतों, नगर पालिका, जिला बोर्ड, छावनी बोर्ड, नगर योजना प्राधिकरण या जिला परिषद को शामिल किया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में एक अध्यक्ष प्रधानमंत्री (पदेन अध्यक्ष) सहित नौ सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय, राज्य और जिला आपदा प्राधिकरण किसी तरह की आपदा का समय पर और प्रभावी निवारण सुनिश्चित करने के लिए कार्यरत रहते हैं। (एन डी एम ए डॉट गॉव डॉट इन) 1। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण नीतियां योजनाएं और मार्ग निर्देशक सिद्धांत बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। यह संस्थान आपदा प्रबंधन के दस्तावेजीकरण और आपदा प्रबंधन की नीति, निवारण तंत्र, शमन के उपायों की रूपरेखा तैयार करता है। इस कानून के तहत एक राष्ट्रीय आपदा संकट मोचन बल का गठन भी किया गया है जो आपदा के समय राहत और बचाव कार्य करता है।

अपराध और दंड विधान --

जो व्यक्ति एनडीआरएफ के कार्य में बाधा डालेगा उसे दोष सिद्ध होने पर 2 वर्ष के कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। यदि कोई जानबूझकर आपदा के समय राहत सहायता मरम्मत निर्माण के लिए गलत दावा या क्लेम करता मिलेगा या मिथ्या जानकारी देगा तो दोष सिद्ध होने पर उसे 2 साल के कारावास की सजा या दंड या दोनों दिया जा सकता है। राहत सामग्री के दुरुपयोग या दुरुपयोग के लिए प्रेरित करने के लिए दोषी होने पर 2 वर्ष की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। जो कोई जिसे किसी आपदा या उसकी गंभीरता या उसके परिमाण के संबंध में आतंकित करने वाली मिथ्या संकट सूचना या चेतावनी देता है तो वह दूषित होने पर कारावास से इसकी अवधि 1 वर्ष की होगी या जुर्माने से दंडनीय होगा।

अब पीड़ित व्यक्तियों को लिंग, जाति, समुदाय या धर्म के आधार पर कोई भेद नहीं किया जाएगा। (एन डी एम ए डॉट गॉव डॉट इन) 12। वस्तुतः आपदा प्रबंधन से तात्पर्य किसी आपदा को आने से रोकने, उसके प्रभाव के स्केल और मात्रा को कम करने, तथा आने के पश्चात किए गए बचाव और सुरक्षा के तौर-तरीकों से है। उदाहरण के तौर पर कोरोना महामारी को लिया जा सकता है जिससे पूरी मानव जाति विश्व स्तर पर इससे अभी तीन साल बाद भी जूझ रही है। देश में अधिकांश जनसंख्या ने इस महामारी का सामना किया है। व्यक्ति, समाज और सरकार के स्तर पर इस महामारी को लेकर एक दैनिक संघर्ष चल रहा है। युद्ध स्तर पर इस महामारी से निपटने के उपाय किए जा रहे हैं। विभिन्न तरह के उपाय, बचाव और सुरक्षा के लिए मीडिया भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यानि व्यक्ति, समाज और सरकार के साथ मीडिया भी सक्रिय है। दूसरे महायुद्ध के बाद दुनिया के समक्ष यह महामारी सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। मुख्यधारा से लेकर सोशल मीडिया कोरोना को लेकर तरह-तरह की सूचनाएं प्रसारित प्रकाशित कर रहा है। फेक वीडियो, टेक्स्ट और फोटो तक परोसी जा रही है लेकिन इसके साथ साथ सकारात्मक सूचनाएं भी बड़ी संख्या में लगातार आ रही हैं जो इस संकट के समय हमें निरंतर आश्वस्त करती रहती हैं। वैश्विक मीडिया ने कोरोना को लेकर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की सूचनाएं संप्रेषित की हैं। आपदा प्रबंधन की सूचना में राजनीति भी एक अहम पक्ष है। जब भी कोई मानवीय, प्राकृतिक या दुर्घटना वश आपदा घटित होती है तो मीडिया में आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला आरंभ हो जाता है। भारत में भोपाल गैस त्रासदी 24 घंटे चलने वाले टेलीविजन चैनलों के आगमन से पूर्व हुई। वस्तुतः 1980 के आसपास ही भारतीय घरों में टेलीविजन का प्रवेश होना आरंभ हुआ था। इसलिए भोपाल त्रासदी की अधिकतर कवरेज समाचार-पत्रों, फोटोग्राफी और वृत्तचित्रों के माध्यम से हुई। (Batabyal Somnath, 115) 3

पिछले तीन दशक में भारत और विश्व भर में प्राकृतिक आपदाओं की संख्या बढ़ी है उसके अनुपात में इन आपदाओं से निपटने का तंत्र भी विकसित करने की दिशा में कार्य हुए हैं। मीडिया में प्रयुक्त उन्नत तकनीक प्राकृतिक आपदा संबंधी पूर्व सूचना संप्रेषण, आपदा के दौरान सहायता और आपदा के उपरांत राहत और बचाव कार्य में उल्लेखनीय योगदान करने लगी है। प्राकृतिक आपदा में मानव जीवन को व्यापक जानमाल की क्षति होती है। ऐसी स्थिति में राहत और बचाव के साथ-साथ व्यापक सहानुभूति और जन संवेदना की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। आपदा के दौरान सरकार और जनता के बीच सूचना संप्रेषण का कार्य अबाधित और पारदर्शी रूप में करने की जिम्मेदारी मीडिया की होती है। भारत सरकार ने आपदा कवरेज के सिद्धहंतों को लेकर एक निर्देशिका भी बनाई है। इस निर्देशिका के अनुसार किसी भी आपदा की रिपोर्टिंग करते समय पत्रकार को सटीक जानकारी देना चाहिए। सभी आंकड़ों और तथ्यों की जानकारी पुष्टि के बाद देनी चाहिए। फोटो और वीडियो फुटेज का चयन भी सावधानी से किया जाना चाहिए। प्रभावित क्षेत्र का भूगोल और पीड़ित जनसमुदाय की पृष्ठभूमि की जानकारी भी मीडिया कर्मियों को होनी चाहिए। आपदा अत्यंत संवेदनशील होती है इसलिए रिपोर्टिंग में शब्दों का चयन सावधानी से किया जाना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट संतुलित और सकारात्मक होनी चाहिए। प्रभावित जनक्षेत्र की गरिमा

, संवेदना और संस्कृति का रिपोर्टिंग करते समय सम्मान किया जाना चाहिए। आपदा और उसके बाद राहत और बचाव कार्यों का की फॉलो अप स्टोरी की जानी चाहिए ताकि सभी प्रभावित पक्षों को राहत सामग्री समय पर प्राप्त हो सके। (एन आई डी एम. गॉव .इन) 4

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और सोशल मीडिया – प्राधिकरण के अंतर्गत जनसम्पर्क और जागरूकता अभियान प्रभाग का गठन किया गया ताकि आपदा की पूर्वसूचना, राहत, बचाव सहित जनता को संवेदनशील बनाया जा सके। इस के माध्यम से जनसम्पर्क प्रभाग उन मामलों को देखता है जिनमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जनता को तैयार करने और सभी हितधारकों, मंत्रालयों, विभागों और राज्यों को संवेदनशील बनाने का काम करता है जो भागीदारों के रूप में आपस में जुड़े हुए हैं। यह कार्य प्राधिकरण क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के व्यापक उपयोग के माध्यम से करता है। ब्रोशर, पम्पलैट, पोस्टर और नुक्कड़ नाटक आदि सरल और लोकप्रिय तरीकों का प्रयोग भी किया जाता है। (एन डी एम ए डॉट गॉव डॉट इन) 5 समय समय पर लोगों को आतंकी घटना, दुर्घटना, युद्ध, संघर्ष, सांप्रदायिक या जाति आधारित हिंसा, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, चक्रवात तूफान, आग, भूकंप, सुनामी, बाढ़, ओलावृष्टि, बादल फटना, बिजली गिरना, शीतलहर, हीटवेव सूखा, भूस्खलन और सुनामी, महामारी, कीट आक्रमण, पशु महामारी जहरीला भोजन रसायनिक और दुर्घटना जनित आपदा जागरूक करने, शमन उपाय, पुनर्वास राहत और बचाव के लिए सेमीनार, कार्यशाला, कॉकलेव और बैठकों का आयोजन किया जाता है। प्राधिकरण आपदा संवाद के माध्यम से मीडिया से जुड़कर आपदा संचार का कार्य करता है।

फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर सक्रियता – राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से आपदा संचार द्वारा निरंतर और नियमित रूप से लोगों से जुड़ा रहता है। प्राधिकरण के नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी, इंडिया फेसबुक पेज पर लगभग रोजाना आपदा संचार से जुड़ी जानकारी साझा की जाती है। इस पेज से लाखों की संख्या में फॉलोवर जुड़े हुए हैं। इस फेसबुक पेज पर आपदा प्रबंधन और संचार के फोटो, टेक्स्ट और वीडियो एनीमेशन और ग्राफिक आदि त्वरित गति से जनता तक पहुंच जाते हैं। एन डी एम ए इंडिया नामक इंस्टाग्राम पेज के हजारों फॉलोवर हैं। इस पेज पर लगभग 790 पोस्ट आपदा सूचना, सलाह, राहत और बचाव के साथ प्राधिकरण के तैयारी बैठकों के वीडियो और फोटोग्राफ्स की अद्यतन जानकारी देते हैं। प्राधिकरण ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया के नाम से एक यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है जिस पर 383 वीडियो अभी तक साझा किए गए हैं। इनमें कोविड, बाढ़, भूकंप, शीतलहर, तूफान, चक्रवात, हिमस्खलन आदि आपदाओं को लेकर सुरक्षा, तैयारी और उपाय से जुड़े वीडियो जनता को सूचित और शिक्षित करते हैं। कोविड और आपदाओं से जुड़ी अनेक लघु फिल्मों भी जनता को शिक्षित करने के लिए इस चैनल पर अपलोड की जाती हैं। त्वरित और संक्षिप्त सूचना प्रदान करने के लिए ट्विटर को एक माध्यम के रूप में प्राधिकरण 2014 से प्रयोग कर रहा है। जनता की प्रतिक्रिया, समस्या और सुझाव की जानकारी प्राप्त करने सबसे बेहतर माध्यम सोशल मीडिया है। आपदा प्रभावित क्षेत्र के लोग सोशल मीडिया पर सही, सटीक और जमीनी जानकारी प्रदान करते हैं। अधिकारियों, सरकार और राहत बचाव दलों तक सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी पहुँच बना सकते हैं। अनेक आपदाओं में सोशल मीडिया ने महावपूर्ण सूचना संचार में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है।

भारत में प्राकृतिक आपदाएं और मीडिया

भारत जैसे देश में बाढ़, अकाल और सूखा प्रतिवर्ष होने वाली प्राकृतिक आपदाएं हैं। पिछले तीन दशक की स्थितियों पर विचार करने पर हम जिन प्रमुख आपदाओं को देखते हैं उसमें 1999 में उड़ीसा में आया तूफान और 2000 में गुजरात और जबलपुर लातूर में आया भूकंप तथा केदारनाथ त्रासदी के साथ केरल और कश्मीर और चेन्नई की बाढ़ उल्लेखनीय है जिनकी मीडिया में व्यापक चर्चा हुई। दरअसल पर्यावरण मुद्दों को केंद्र में लाने में टेलीविजन कार्यक्रम ग्रीनार्थोन की अनदेखी नहीं की जा सकती। 2009 में भारत के प्रमुख न्यूज नेटवर्क एन डी टी वी ने पर्यावरण मुद्दों पर लाइव धन संग्रह करने के लिए ग्रीनार्थोन नामक कार्यक्रम का आयोजन किया। और ग्रीनार्थोन भारत का सबसे बड़ा टी वी पर्यावरण इवेंट बन गया है। (Batabyal Somnath, 59) 6 पर्यावरण संरक्षण को लेकर मीडिया और न्यायिक स्तर पर भी सक्रियता दिखाई देती है। जब भी कोई आपदा या संकट की स्थिति उत्पन्न होती है तब न्यायिक और मीडिया में अति सक्रियता का माहौल दिखाई देता है। अभी तक देश में पर्यावरण को लेकर उच्चतम न्यायालय के 18, उच्च न्यायालय के भी 18 देश और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के 8 आदेश पारित हो चुके हैं। सरकार के स्तर पर पर्यावरण को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने के उच्चतम न्यायालय के आदेश को लागू करने में एक दशक से ज्यादा का समय लगा। इससे सरकारी स्तर पर पर्यावरण को लेकर गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है।

संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन जीने के अधिकार के तहत स्वच्छ वातावरण में जीने का अधिकार भी शामिल है, किंतु मीडिया में पर्यावरण विज्ञापन के द्वार नहीं खोलता इसलिए पर्यावरण की उपस्थिति इतनी गंभीरता से नहीं ली जाती है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने का दावा करने वाले मीडिया की जिम्मेदारी है कि वह पर्यावरण के प्रति लोगों को शिक्षित, सूचित और जागरूक करने की भूमिका को जिम्मेदारी से और गंभीरता से निभाए। भारत जैसे देश में आबादी के एक बड़े हिस्से में अभी भी पर्यावरण को लेकर एक तरह की उदासीनता जागरूकता और संरक्षण का अभाव है। सोशल मीडिया ने एक वैकल्पिक रूप में स्थानीय स्तर पर पर्यावरण और प्राकृतिक आपदाओं की वास्तविक तस्वीर सामने लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

आपदा के तीन स्तर और मीडिया -- मुख्यधारा के मीडिया में भूमंडलीकरण के बाद पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं पर लगातार चिंता व्यक्त की जाती रही है। प्राकृतिक आपदाओं के संदर्भ में मीडिया की भूमिका को तीन स्तर पर देखा जा सकता है। प्रथम आपदा के आने पूर्व की तैयारी, आपदा के दौरान निभाई गई भूमिका और आपदा के बाद की परिस्थितियों में मीडिया की भूमिका। तीनों स्तर पर मीडिया का जिम्मेदार रोल होता है। किसी भी स्तर पर थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। सूचना का प्रमुख सिद्धांत नैतिक होना चाहिए इसलिए संकट के समय प्रभावित क्षेत्र में लोगों की जरूरतों के अनुसार संवेदनशील होना चाहिए। मीडिया को भय और चिंता फैलाने वाली भ्रामक और अपुष्ट रिपोर्ट प्रकाशित प्रसारित नहीं करनी चाहिए। किसी भी अनिष्ट के संभावित प्रभाव को संतुलित करने के लिए मीडिया के माध्यम से सही और विश्वसनीय सूचना एक महत्वपूर्ण उपकरण है। (<https://ijcrt.org>, April, 2018) 7 सोशल मीडिया में भी लगातार पर्यावरण चिंतक और आम नागरिकों के द्वारा दबाव बनाने का प्रयास होता रहा है कि विकास

की नीतियां पर्यावरण हितैषी बनाई जाए जिससे कि पर्यावरण को ध्यान में रख कर विकास हो और कम से कम आपदाएं घटित हों। इस दिशा में विकसित देशों को अपनी भूमिका और जिम्मेदारी को सक्रियता से निभाना चाहिए। कुछ समय पूर्व ग्रेटा थंबर्ग की पर्यावरण संबंधित चिंताओं को लेकर मीडिया में अच्छी कवरेज दी गई। सोशल मीडिया में लगातार ग्रेटा के सवालियों पर बहस होती दिखाई दी। ग्रेटा ने पर्यावरण को लेकर एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर विकसित देशों के दोहरे चरित्र को उजागर कर उन्हें कटघरे में खड़ा करने का साहस दिखाया। दुनिया भर के मीडिया ने उनकी तारीफ के पुल बांध दिए।

विकास , पर्यावरण और मीडिया --- भारत में पर्यावरण संकट के चलते प्राकृतिक आपदाएं समाज जीवन के प्रत्येक हिस्से को प्रभावित कर रही हैं। बढ़ते औद्योगिकीकरण , शहरीकरण और जनसंख्या भारत जैसे देशों के लिए अवसर और चुनौती दोनों रूपों में सामने आ रहे हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि पृथ्वी हम मनुष्य की जरूरत को पूरा करती है किंतु हर मनुष्य के लालच को नहीं। विश्व स्तर पर लगातार बिगड़ते पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर पर्यावरणविद लगातार चिंता व्यक्त करते रहे हैं। आपदा 80 के दशक में पश्चिमी देशों में तेजी से हुए औद्योगिकीकरण के कारण पर्यावरण पर बहुत बुरा असर पड़ा। वहां पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर आवाज उठनी आरंभ हुई। नागरिकों में पर्यावरण चेतना पैदा करने और उसके प्रति जागरूक बनाने की शुरुआत हुई। दुनिया 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाए जाने की शुरुआत हुई। विश्व पर्यावरण दिवस पर सरकार , पर्यावरणविद और मीडिया अपने अपने स्तर पर चिंता पर्यावरण को लेकर चिंता साझा करते हैं।

पत्र पत्रिकाओं में स्थिति -- भारत के मुख्यधारा के पत्रों और चैनलों में पर्यावरण को लेकर कोई गंभीर चिंता नहीं दिखाई देती है। पर्यावरण की नियमित रिपोर्टिंग कम ही पत्र या चैनलों में मौजूद है। पत्रकारों को आपदा के समय किस प्रकार रिपोर्टिंग करनी चाहिए इसके लिए मीडिया संस्थानों में उचित ट्रेनिंग और मैनेजमेंट का भी अभाव है। यही कारण है कि आपदा के समय किसी भी रिपोर्टर को रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी दे दी जाती है। ऐसी रिपोर्टर के पास आपदा की समुचित जानकारी और रिपोर्टिंग की ट्रेनिंग का अभाव होने के चलते रिपोर्टिंग में सनसनी या अति उत्साही ज्यादा दिखाई देता है। आपदा का समय काफी संवेदनशीलता की मांग करता है। पत्रकार टी वी शिवनंदन के अनुसार हाल के वर्षों में मास मीडिया ने प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व चेतावनी और कवरेज के माध्यम से लोगों को सबसे प्रभावशाली ढंग से संवेदनशील बनाने में मदद की है। (The Hindu , 19/02/2020) 8 चक्रवात, तूफान ,बाढ़ ,भूमि कटाव ,सूखा जलभराव, सुनामी, प्रदूषण जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय ज्यादातर मीडिया विशेषज्ञों के भरोसे ही रिपोर्टिंग का काम कर लिया जाता है। पर्यावरण विषय के जानकार पत्रकारों का अभी भी हिंदी मीडिया में खासा अभाव है।

खोजी रिपोर्ट और फॉलोअप का अभाव

प्राकृतिक आपदाओं की रिपोर्ट में मीडिया में आंकड़ों की संख्या पर ज्यादा जोर रहता है। आपदा के कारण और आगामी समाचारों का फॉलोअप घटना के कुछ दिन बाद गायब हो जाता है। प्राकृतिक आपदाओं की रिपोर्टिंग में घटना की संभावना को लेकर हिंदी मीडिया में खोजी रिपोर्ट का अभाव दिखाई देता है। जहां तक प्रतिवर्ष गठित होने वाली तूफान ,बाढ़ ,आगजनी जैसी आपदाओं का प्रश्न है तो मीडिया में सरकारी एडवाइजरी और विज्ञापन प्रकाशित कर जिम्मेदारी का निर्वाह कर दिया जाता है। कभी-कभी एनडीएमए की ओर से राज्य सरकारों द्वारा चलाए जाने वाले जागरूकता अभियानों और रैलियों की खबरें अखबारों के महानगर के पन्नों पर किसी कोने में चस्पा दी जाती हैं।

सोशल मीडिया में तेज और ज्यादा जानकारी लेकिन विश्वसनीयता कमजोर -

पर्यावरण आपदा की जानकारी मुख्यधारा मीडिया से ज्यादा सोशल मीडिया में अधिक विविधता और व्यापकता से मिल रही है। कश्मीर या केरल की बाढ़ हो या दिल्ली का स्मॉग या कोरोना। सोशल मीडिया पर इनसे जुड़ी खबरें मुख्यधारा के मीडिया के मुकाबले ज्यादा रहीं। दरअसल सोशल नेटवर्किंग साइट दुधारी तलवार है जिसमें फेक फैक्ट्री भी समानांतर रूप से चल रही होती है। इसलिए फेक चेक यूनिट ज्यादातर मीडिया घरानों ने अनिवार्य रूप से बना रखी है। गलत , भ्रामक जानकारी और अफवाहों को रोकने का मेकैनिज्म सोशल मीडिया के पास नहीं है। आपदा के समय यह फेक जानकारी नए तरह के संकट को पैदा कर सकती है। किसी भी तरह की अफवाह-तफरी की संभावना पैदा होने का खतरा अक्सर रहता है। इसलिए सरकार के स्तर पर अब भी सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है और इस तरह की अफवाहों और भ्रामक जानकारियों का खंडन नियमित तौर पर समय-समय पर किया जाता है। खासतौर पर आपदा के समय सरकारी न्यूज चैनल समितियां और सरकारी सोशल प्लेटफॉर्म अधिक भरोसेमंद माने जाते हैं। सोशल मीडिया पर आजकल इंफोडेमिक यानि गलत खबरों के प्रचार -प्रसार को लेकर कोई कानून नहीं है। इसलिए आपदा संचार में बहुत-सी झूठी जानकारी और तथ्य आते रहे हैं। सटीक और विश्वसनीय जानकारी के अभाव में जोरिखम बढ़ने की संभावना रहती है। द वायर की रिपोर्ट के अनुसार संकट के समय सटीक जानकारी की बढ़ती आवश्यकता के साथ एक व्यक्ति की सही और गलत जानकारी के बीच अंतर करने में असमर्थता के कारण इंफोडेमिक तेजी से फैलता है। (द वायर .16-02-2023) 9 तुर्की सीरिया भूकंप इसके उदाहरण हैं। सोशल मीडिया आपदा राहत में सबसे पहले सूचनाएं देने का माध्यम बन कर उभरा है। प्राकृतिक आपदाओं के समय लोग सोशल मीडिया का उपयोग कई कारणों से करते हैं। --परिवार और दोस्तों से मिलने के लिए, सहायता प्राप्त करने के लिए , आपदा की भयावहता के बारे में समाचार एकत्र करने के लिए और ग्राउंड जीरो की सीधी रिपोर्टिंग के लिए। राहत और बचाव में सुधार के अलावा लोग दान भेजने के लिए भी सोशल नेटवर्किंग साइट का उपयोग कर सकते हैं। (डाउन टू अर्थ , विजदान सलीम) 10 .

मंत्रालय , नौकरशाही और मीडिया - पिछले कुछ वर्षों में सरकारी मंत्रालय और विभाग सहित प्रधानमंत्री और मंत्री सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर जानकारियां देकर लोगों को आश्वस्त करते हैं। पिछले एक दशक से टिविटर त्वरित आपदा प्रबंधन सूचना का सर्वाधिक पसंदीदा मंच बना हुआ है जहां किसी प्राकृतिक आपदा के विविध आयामों पर एक साथ सरकार , नौकरशाही , एन जी ओ , परामरागत मीडिया , पर्यावरण विशेषज्ञ , वैज्ञानिक , सहायता कर्मी स्वास्थ्य कर्मी आदि से लेकर आम नागरिक और प्रभावित जन सक्रिय होकर अपनी राय, सुझाव, पीड़ा, चेतावनी और आलोचना को साझा करते हैं। पर्यावरण आपदा प्रबंधन की जानकारी के लिए मीडिया में सरकार की ओर से मदद के लिए विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाते हैं। आपदा के समय खासतौर पर महामारी के समय चैनल , समाचार पत्रों और सोशल मीडिया पर सामग्री की बाढ़

सी आ जाती है। समाचार पत्रों, टीवी चैनल और सोशल मीडिया पर ऐसे समय क्या करें क्या ना करें की सलाह, विशेषज्ञों की सलाह, सरकारी एडवाइजरी और अन्य अद्यतन सूचनाएं नियमित और निरंतर रूप से दी जा रही होती हैं। केदारनाथ त्रासदी की खबर समाचार पत्रों में वर्षों पूर्व की गई थी प्रकाशित की गई थी लेकिन उस समय उस पर ध्यान नहीं दिया गया। भारतीय मीडिया के पास बीबीसी की तरह साधन नहीं है कि वह सीधे अंटार्कटिका में शोध कर रहे वैज्ञानिकों के साथ रिपोर्ट्स की टीम भेजकर सीधे जानकारी हासिल कर ले और ये जानकारी जनता को उपलब्ध कराएं जिससे आने वाले समय में समुद्र किनारे के कई शहर जलमग्न हो सकते हैं। एनडीटीवी की 31 अगस्त 2022 की रिपोर्ट के अनुसार सरकार अपनी आपदा चेतावनी प्रणाली का विस्तार कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार सी डॉट ने आपदा चेतावनी का पहला चरण पूरा कर लिया है। जिसमें सभी राज्य बोर्ड पर या गए हैं। सभी राष्ट्रीय अलर्ट देने वाली एजेंसियां—भारत मौसम विज्ञान विभाग, केन्द्रीय जल आयोग, भारतीय राष्ट्रीय समुद्र सूचना केंद्र, रक्षा भू सूचना केंद्र, अनुसंधान प्रतिष्ठान और भारतीय वन सर्वेक्षण इसमें शामिल हो गए हैं। अलर्ट भेजने के लिए रेडियो स्टेशन, डी टी एच प्लेयर और रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया है। (एनडीटीवी 31 अगस्त, 2022) 11

वैश्विक आपदा में पश्चिमी मीडिया पर निर्भरता

भारतीय समाचार पत्र पर्यावरण की जानकारी के लिए वैश्विक समाचार समितियों या पश्चिमी मीडिया पर ही निर्भर है। भारत जैसे देश में आम आदमी आम तौर पर मीडिया पर भरोसा करता है। गलत जानकारी होने के कारण नुकसान का अंदेश रहता है यदि ऐसी जानकारियों का समय पर खंडन न किया जाए तो बहुत अफरा-तफरी हो सकती है लेकिन सरकार भी अब सोशल मीडिया पर निरंतर सक्रिय हैं और अपने सोशल मीडिया नेटवर्क के माध्यम से अद्यतन इस तरह की गलत जानकारियों का खंडन मिलता देखा गया है जब तक खंडन या स्पष्टीकरण आता है तब तक नुकसान हो चुका होता है। जापानी फ्लू की दवा कोरोना जैसी महामारी में कारगर होने का दावा भी सोशल मीडिया पर खासा चर्चित रहा लेकिन सरकार ने समय रहते ही खंडन किया कि अभी तक इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। सरकार की तरफ से स्वास्थ्य मंत्रालय ने हर राज्य के डिजिस्ट्र राहत कोष को इस्तेमाल करने की छूट दी है तथा फेक न्यूज़ से सावधान रहने और घबराहट में जमाखोरी न करने की सलाह भी दी है। समाचार पत्र टीवी चैनल के साथ सरकार भी सोशल मीडिया पर अद्यतन जानकारी उपलब्ध करा रही है सरकार ने व्हाट्सएप नंबर जारी करके लोगों को जानकारी शेयर करने का एक मंच प्रदान किया है।

आपदा प्रबंधन रिपोर्टिंग: जोखिम के साथ जनहित --

आपदा प्रबंधन में मीडिया की भूमिका ज्यादा जोखिम पूर्ण है अतः उसे बेहद सावधानी और चौकन्ना होकर काम करना पड़ता है। आपदा के कठिन समय में मीडिया को चौतरफा और गहन जानकारी रखनी पड़ती है। उसे खुद को भी बचाना है और समाज को भी जागरूक करना होता है। आपदा के समय सूचना स्रोत की विश्वसनीयता जानना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। कोरोना महामारी के समय यह देखा गया है कि लोग बिना सूचना की पुष्टि के जानकारी को सोशल मीडिया पर तुरंत शेयर कर देते हैं। इतनी बड़ी आबादी वाले देश में ऐसी सूचनाओं का गलत प्रभाव पड़ने की व्यापक संभावना रहती है क्योंकि गलत जानकारी और सूचनाएं व्यापक सामाजिक नुकसान कर सकती हैं समाज में अफरा तफरी और खौफ का वातावरण पैदा कर सकती हैं। न्यूज़ लांड्री की एक रिपोर्ट में जोशीमठ रिपोर्टिंग में मीडिया के लिए कहा कि मीडिया आपदा रिपोर्टिंग में उस संदेश की अनदेखी कर रहा है, वह संदेश है कि अगर आप किसी आपदा को रिपोर्ट करते हैं तो उन दृष्टिकोणों को एकीकृत करें जो इसके कारणों की व्याख्या करते हैं। (न्यूज़ लांड्री, 12-01-2023) 12.

कोरोना आपदा में मीडिया

ऐतिहासिक कोरोना आपदा के समय राहत और बचाव के काम में भी मीडिया की भूमिका उल्लेखनीय होती है। कोरोना के समय मास्क, सैनिटाइजर, स्वास्थ्य, दवा राशन, परिवहन की जानकारियां समय-समय पर प्रदान कर मीडिया ने एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। ब्रेकिंग और टीआरपी की दौड़ टीवी चैनलों पर हावी है लेकिन रेडियो और दूरदर्शन ज्यादा गंभीरता से अपने काम को कर रहे हैं। अंत में उल्लेखनीय है कि भारत में आज से दो दशक पूर्व आपदा को लेकर मीडिया में पुश फैक्टर पर काम करता था अब तकनीक और प्रौद्योगिकी के आने के बाद मीडिया में जानकारी और खबरें आने का सिलसिला आपदा से पहले ही आरंभ हो जाता है। तकनीकी और प्रौद्योगिकी विकास के चलते व सोशल मीडिया के कारण परंपरागत मीडिया न्यूज़ रूम और उसकी प्राथमिकता भी बदली है। अब मीडिया में सूचनाएं तुरंत आने लगती हैं और सोशल मीडिया में तो हर सेकेंड सूचनाओं का अंबार लगा रहता है। मीडिया में संभावित आपदाओं को चिन्हित कर आपदा पूर्व जानकारियां भी उपलब्ध हो रही हैं यह मीडिया में निश्चित रूप से एक उल्लेखनीय बदलाव है। इंफोडेमिक के दौर में कोविड को लेकर सही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिंता व्यक्त करते हुए लिखा कि कोविड 19 महामारी के सामने आने से पता चलता है कि कैसे सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फैलाई जा रही गलत सूचनाओं का प्रसार वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्यके लिए उतना ही खतरनाक साबित हो रहा है जितना कि स्वयं वायरस। (WHO, वेबसाइट) 13। कोई सोशल मीडिया संबंधी कानून न होने से अफरा तफरी का वातावरण—सा बन गया था और अफावहों और गलत सूचनाओं का अंबार—सा लग गया था। सोशल मीडिया के दुरुपयोग के बावजूद कोविड में इसके महत्वपूर्ण योगदान की अनदेखी नहीं की जा सकती है। अमर उजाला की 22 अप्रैल 2021 की रिपोर्ट के अनुसार शायद कोई सोशल मीडिया अकाउंट होगा जिससे किसी की मदद के लिए कोई पोस्ट नहीं किया होगा। कोई व्हाट्सएप के जारी, कोई फ़ेसबुक के जारी तो कोई ट्विटर के जारी ऑक्सीजन सिलेंडर रेमीडिसेवर, फेविफ्लु, बैड आदि के लिए मदद मांग रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो भारत में कोरोना के खिलाफ जंग सोशल मीडिया में लड़ी जा रही है। सोशल मीडिया का इस तरह से इस्तेमाल शायद ही भारत में कभी हुआ हो। (अमर उजाला, 22-04-2021) 14

निष्कर्ष -- आपदा आरंभ से ही मानव जीवन से जुड़ी है। वस्तुतः आपदा किसी क्षेत्र में हुए उस विध्वंस, अनिष्ट, विपत्ति या बेहद गंभीर घटना से है जो प्राकृतिक या मानवीय कारणों से दुर्घटना वश या लापरवाही से घटित होती है। आपदा के कारण मनुष्य जीवन, संपत्ति और पर्यावरण तीनों प्रभावित होते हैं। आपदा की विकट स्थिति मानवीय, भौतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन पर विपरीत प्रभाव डालती है। प्राकृतिक आपदाओं के संदर्भ में मीडिया की भूमिका को तीन स्तर पर देखा जा सकता है। प्रथम आपदा के आने पूर्व की तैयारी, आपदा

के दौरान निभाई गई भूमिका और आपदा के बाद की परिस्थितियों में मीडिया की भूमिका। तीनों स्तर पर मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पिछले तीन दशक में भारत और विश्व भर में प्राकृतिक आपदाओं की संख्या बढ़ी है उसके अनुपात में इन आपदाओं से निपटने का तंत्र भी विकसित करने की दिशा में कार्य हुए हैं।

मीडिया में प्रयुक्त उन्नत तकनीक प्राकृतिक आपदा संबंधी पूर्व सूचना सम्प्रेषण, आपदा के दौरान सहायता और आपदा के उपरांत राहत और बचाव कार्य में उल्लेखनीय योगदान करने लगी है। भारत के मुख्यधारा के पत्रों और चैनलों में पर्यावरण को लेकर कोई गंभीर चिंता नहीं दिखाई देती है। पर्यावरण की नियमित रिपोर्टिंग कम ही पत्र या चैनलों में मौजूद है। पत्रकारों को आपदा के समय किस प्रकार रिपोर्टिंग करनी चाहिए इसके लिए मीडिया संस्थानों में उचित ट्रेनिंग और मैनेजमेंट का भी अभाव है। यही कारण है कि आपदा के समय किसी भी रिपोर्टर को रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी दे दी जाती है। पर्यावरण आपदा की जानकारी मुख्यधारा मीडिया से ज्यादा सोशल मीडिया में अधिक विविधता और व्यापकता से मिल रही है। कश्मीर या केरल की बाढ़ हो या दिल्ली का स्मॉग या कोरोना। सोशल मीडिया पर इनसे जुड़ी खबरें मुख्यधारा के मीडिया के मुकाबले ज्यादा रहीं। दरअसल सोशल नेटवर्किंग साइट दुधारी तलवार है जिसमें फेक फैक्ट्री भी समानांतर रूप से चल रही होती है इसलिए फेक चेक यूनिट ज्यादातर मीडिया घरानों ने अनिवार्य रूप से बना रखी है। गलत, भ्रामक जानकारी और अफवाहों को रोकने का मैकेनिज्म सोशल मीडिया के पास नहीं है। भारतीय समाचार पत्र पर्यावरण की जानकारी के लिए वैश्विक समाचार समितियों या पश्चिमी मीडिया पर ही निर्भर है। भारत जैसे देश में आम आदमी आम तौर पर मीडिया पर भरोसा करता है। गलत जानकारी होने के कारण नुकसान का अंदेश रहता है यदि ऐसी जानकारियों का समय पर खंडन न किया जाए तो बहुत अफरा-तफरी हो सकती है लेकिन सरकार भी अब सोशल मीडिया पर निरंतर सक्रिय हैं और अपने सोशल मीडिया नेटवर्क के माध्यम से अद्यतन इस तरह की गलत जानकारियों का खंडन मिलता देखा गया है। पिछले कुछ वर्षों में सरकारी मंत्रालय और विभाग सहित प्रधानमंत्री और मंत्री सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर जानकारियां देकर लोगों को आश्वस्त करते हैं। पिछले एक दशक से ट्विटर त्वरित आपदा प्रबंधन सूचना का सर्वाधिक पसंदीदा मंच बना हुआ है जहां किसी प्राकृतिक आपदा के विविध आयामों पर एक साथ सरकार, नौकरशाही, एन जी ओ, परामरागत मीडिया, पर्यावरण विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, सहायता कर्मी स्वास्थ्य कर्मी आदि से लेकर आम नागरिक और प्रभावित जन सक्रिय होकर अपनी राय, सुझाव, पीड़ा, चेतावनी और आलोचना को साझा करते हैं। जनता की प्रतिक्रिया, समस्या और सुझाव की जानकारी प्राप्त करने सबसे बेहतर माध्यम सोशल मीडिया है। आपदा प्रभावित क्षेत्र के लोग सोशल मीडिया पर सही, सटीक और जमीनी जानकारी प्रदान करते हैं। अधिकारियों, सरकार और राहत बचाव दलों तक सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी पहुँच बना सकते हैं। अनेक आपदाओं में सोशल मीडिया ने महत्वपूर्ण सूचना संचार में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। भारत जैसे देश में आबादी के एक बड़े हिस्से में अभी भी पर्यावरण को लेकर एक तरह की उदासीनता है। अधिकांश आबादी में पर्यावरण के प्रति जागरूकता और संरक्षण को लेकर चिंता का अभाव है। ऐसी स्थिति में सोशल मीडिया ने एक वैकल्पिक रूप में स्थानीय स्तर पर पर्यावरण और प्राकृतिक आपदाओं की वास्तविक तस्वीर सामने लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

संदर्भ

1. <https://ndma.gov.in>
2. <https://ndma.gov.in>
3. Batabyal, Somnath .(2021).Environment ,Politics and Activisim and Role of Media,Delhi:Routledge,115
4. <https://nidm.gov.in>
5. <Http://ndma.gov.in>
6. Batabyal, Somnath .(2021).Environment ,Politics and Activisim and Role of Media,Delhi:Routledge,59
7. <https://ijcrt.org> Role of social media in disaster management sarita Bansal ,April ,2018.
8. द हिन्दू . (2020). <https://www.thehindu.com/news/national/karnataka/role-of-media-in-disaster-management-highlighted/article30857466.ece>
The Hindu 19/02/2020)
9. द वायर . (2023). <https://thewire.in/media/media-coverage-after-a-disaster-lessons-from-turkey>
10. डाउन टू अर्थ . <https://www.downtoearth.org.in/blog/how-people-turn-to-social-media-during-natural-disasters-49587>
11. एनडीटीवी . (2022). <https://www.ndtv.com/india-news/government-to-expand-disaster-warning-system-to-use-tv-radio-railway-station-for-alerts-3303755>
12. न्यूज़ लांड्री . (2023). <https://www.newslaundry.com/2023/01/12/joshimaths-story-dates-back-decades-thats-why-media-must-dig-deep>
13. <https://www.who.int>
14. अमर उजाला . (2021). <https://www.amarujala.com/technology/social-network/covid-19-india-social-media-like-twitter-and-facebook-are-playing-a-major-role-to-fight-against-coronavirus>